सीएसईपी वर्किंग पेपर-16
अक्टूबर 2021

Centre for Social and Economic Progress
CSEP
Independence | Integrity | Impact

2030 में भारत

भारत का आगामी दशक:

कुछ भविष्यवाणियां, कुछ अनुमान

गौरव डालमिया

कॉपीराइट © गौरव डालमिया

दी सेंटर फॉर सोशल एंड इकनोमिक प्रोग्रेस (CSEP)
CSEP रिसर्च फाउंडेशन
6, डॉ जोस पी. रिज़ल मार्ग, चाणक्यपुरी, नई
दिल्ली - 110021, भारत

अनुशंसित उद्धरण:
डालमिया जी। (2021)। *भारत का आगामी दशक: कुछ भविष्यवाणियां, कुछ अनुमान*(CSEP वर्किंग पेपर 16)। नई दिल्ली: दी सेंटर फॉर सोशल एंड इकनोमिक प्रोग्रेस

दी सेंटर फॉर सोशल एंड इकनोमिक प्रोग्रेस (CSEP) गहन नीति-प्रासंगिक अनुसंधान करता है और भारत और दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए साक्ष्य-आधारित सिफारिशें प्रदान करता है। यह अनुसंधान के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपने शोधकर्ताओं की विशेषज्ञता, नीति निर्माताओं के साथ व्यापक चर्चा के साथ-साथ संयोजन शक्ति पर निर्भर करता है। CSEP नई दिल्ली में स्थित और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत शेयरों द्वारा सीमित और गैर लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है।

सभी सामग्री लेखकों के व्यक्तिगत विचारों को दर्शाती है। दी सेंटर फॉर सोशल एंड इकनोमिक प्रोग्रेस (CSEP) अपना किसी भी विषय पर संस्थागत दृष्टिकोण नहीं रखता है।

CSEP वर्किंग पेपर चर्चा और टिप्पणी के उद्देश्यों के लिए परिचालित किए जाते हैं। यहां व्यक्त किए गए विचार लेखकों के अपने विचार हैं। सर्वाधिकार सुरक्षित है। पाठ के छोटे खंड जो दो अनुच्छेदों से अधिक नहीं होने चाहिए, उन्हें स्पष्ट अनुमति के बिना उद्धृत किया जा सकता है, बशर्ते कि कॉपीराइट नोटिस सहित स्रोत को पूरा क्रेडिट दिया गया हो।

मुकेश रावत द्वारा डिजाइन किया गया

2030 में भारत

भारत का आगामी दशक:

कुछ भविष्यवाणियां, कुछ अनुमान

गौरव डालमिया*
दी सेंटर फॉर सोशल एंड इकनोमिक प्रोग्रेस
नई दिल्ली, भारत

गौरव डालमिया दी सेंटर फॉर सोशल एंड इकनोमिक प्रोग्रेस में निदेशक मंडल के सदस्य और डालमिया ग्रुप ऑफ होल्डिंग्स के अध्यक्ष हैं। यहाँ व्यक्त किये गए विचार लेखकों के अपने विचार हैं दी सेंटर फॉर सोशल एंड इकनोमिक प्रोग्रेस (CSEP) किसी भी विषय पर अपना संस्थागत दृष्टिकोण नहीं रखता है।

विषयसूची

1. भारतीय उपभोक्ता का परिचालन उत्तोलन एक प्रबल शक्ति होगा 5

2. संरचनात्मक अवरोध और बाधाएं जारी रहेंगी 7

3. स्मार्ट नीति समाधान और स्वामित्व की भावना महत्वपूर्ण होगी 8

4. कार्रवाई राजनीति और अर्थशास्त्र के चौराहे पर होगी 10

5. निष्कर्ष: जीतने के लिए, कैथेड्रल सोच का अभ्यास करें.....11

संदर्भ 13

परिशिष्ट.....14

तालिकाओं की सूची

तालिका 1: उपभोक्ता टिकाऊ सूचकांक 14

तालिका 2: विभिन्न देशों में गिनी इंडेक्स 14

तालिका 3: निवेश जीडीपी के % में 15

2030 में भारत

भारत का आगामी दशक:

कुछ भविष्यवाणियां, कुछ अनुमान

हमारी अधिकांश बहसें यहाँ, वर्तमान स्थिति जैसे कि: कोविड -19 चुनौतियां, चीन के साथ सीमा विवाद, कृषि विधेयक, पेगासस द्वारा फोन हैकिंग या बैंकिंग क्षेत्र के निरंतर खराब ऋण संकट जैसे मुद्दों पर केंद्रित हैं। हालाँकि सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों के साथ-साथ सबसे आशाजनक अवसर वे हैं जिन्हें अर्थशास्त्री "क्षितिज से परे" समस्याएं कहते हैं। सरीसृप मस्तिष्क से हमारे विकास और हमारी कड़ी अस्तित्व प्रवृत्ति को धन्यवाद, कि हम व्यवस्थित रूप से वर्तमान चुनौतियों की भयावहता को बढ़ा-चढ़ा कर आंकते है और उन चुनौतियों को, जो बहुत दूर हैं कम करके आंकते हैं।

यह वर्ष भारत के बहुप्रतीक्षित आर्थिक सुधारों की तीसवीं वर्षगांठ है। तब से बहुत कुछ बदल चुका है। आजादी के शुरुआती दशकों में भारत ने गरीबी को आत्मसात कर लिया था। इस बहस में कि संसाधनों की कमी और व्यय की शून्य राशि की प्रकृति के कारण सब्सिडी या बुनियादी ढांचा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए या नहीं, अक्सर सब्सिडी को प्राथमिकता दी जाती थी और दीर्घकालिक निवेश पिछड़ जाता था। "हिंदू विकास दर" जिसका परिणाम 1.3% प्रति व्यक्ति वृद्धि के रूप में हुआ था, शुरुआती दशकों में भारत की स्वतंत्रता के बाद के प्रदर्शन को परिभाषित करने के लिए उपयोग होता था, (देखें विरमानी, (2004))[1]। आज का भारत अपनी वास्तविकता में और अपनी आकांक्षाओं में भी, प्रभावी रूप से काफी भिन्न है। राल्फ वाल्डो इमर्सन की कही बात बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने कहा: "वर्षों के दौरान हम बहुत कुछ सीख चुके होते हैं जिनके बारे में दिनों में कुछ भी पता नहीं चलता है।" मेरा निष्कर्ष है कि वर्षों तक वे कहानियां छिपी रहती हैं जिनके बारे में केवल दशकों में ही पता चल सकता है।

यह निबंध एक दशक आगे देखने का प्रयास करेगा। मैं इसमें उन मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करूंगा, जो कि मुझे विश्वास है, हमारे देश के लिए 'गेम चेंजर' हो सकते हैं। इनका मार्गदर्शन करने के लिए केवल ठोस तर्कसंगत विश्लेषण की ही नहीं होगी बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता होगी। और इससे भी बढ़कर इसके लिए समाज के विविध अंगों को भी तैयार करने की आवश्यकता होगी। ये सब मिलकर हमें आगे बढ़ाएंगे। जब हम आने वाले दशक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब अब्राहम लिंकन की भविष्यदर्शी अंतर्दृष्टि को याद करना उपयोगी होगा: "अपने भविष्य का निर्माण करना, इसकी भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका है।"

1. भारतीय उपभोक्ता का परिचालन उत्तोलन एक प्रबल शक्ति होगी

जिस समय आर्थिक परिस्थितियों में अपरिहार्य उतार-चढ़ाव हो रहे होंगे, उसी समय एक मजबूत एक दिशा में बहने वाली अनुकूल हवा (यूनिडायरेक्शनल टेलविंड) भी मौजूद होगी जो अत्यंत अनुकूल होगी। मैं इसे भारतीय उपभोक्ता का परिचालन उत्तोलन कहता हूँ। अधिकतर भारतीयों के वार्षिक आय के प्रत्येक 100 रुपये में से 80 रुपये दिन-प्रतिदिन के व्ययों पर खर्च हो जाते हैं। शेष बचे हुए 20 रुपये ही वह आय है, जिसे विवेकाधीन आय कहा जा सकता है। यदि भारत में मामूली वेतन वृद्धि 9%[2] है, जो कि एक औसत वृद्धि रही है, और यदि इसमें से 4% मुद्रास्फीति घटा दी जाती है तो वास्तविक वेतन वृद्धि सिर्फ 5% होगी। वास्तविकता में, आय में सालाना औसत बढ़ोत्तरी मात्र 105 रुपये ही होती है। हालाँकि औसत विवेकाधीन आय 20 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो जाती है जो कि 25% की वृद्धि होती है। हम लाखों भारतीय लोगों के बारे में जानते हैं जो इस सीमा को पार कर गए हैं, जहां उनके वेतन में 8-10% की सीमा में मामूली वृद्धि होती है, लेकिन वास्तविकता में उनकी विवेकाधीन आय 20% की दर से बढ़ रही है।

व्यापार चक्र इस प्रवृत्ति को केवल अल्पावधि के लिए कुछ हद तक ही वश में कर सकते हैं। मध्यम अवधि में और निश्चित रूप से लंबी अवधि में भी, यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से बनी रहेगी। इसके परिणाम काफी गहरे हैं। यहाँ एक नमूना दिया गया है: वर्ष 2010-2020 के दशक में निजी सामान्य बीमाकर्ताओं ने 18.5 प्रतिशत और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 21.2% की वृद्धि हासिल की है[3], क्योंकि उनकी सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता के कारण बाजार में उनकी पैठ में वृद्धि हुई और बाजार में हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से खिसक कर निजी बीमा कंपनियों के हिस्से में चली गई है। कोविड 19 द्वारा उत्पन्न व्यवधान को छोड़कर, विज्ञापन वृद्धि ने - जो एक प्रत्यक्ष उपभोक्ता प्रॉक्सी है - पिछले एक दशक में 12% वार्षिक वृद्धि की दर दर्ज किया है[4]। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में भी वर्ष 2012-2020 के दौरान 20% की वृद्धि देखी गई है।

---

1 देखें http://www.financialexpress.com/archive/redefining-the-hindu-rate-of-growth/104268/

2 http://www.thehindubusinessline.com/economy/at-92-salary-growth-in-india-is-highest-in-asia/article30462524.ece

3 भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का डेटा देखें

4 देखें पिच मैडिसन विज्ञापन रिपोर्ट 2019, जो यहां उपलब्ध हैं https://www.exchange4media.com/PMAR19-Final.pdf

कंपनी-विशिष्ट संख्याएं भी समान रुझान दिखाती हैं: टेलीकॉम कंपनी Jio के वायरलेस ग्राहकों की संख्या 2017-2018 के अंत में 186.6 मिलियन से बढ़कर 2019-2020 के अंत में 387.5 मिलियन हो गई[5] और इसके आक्रामक मूल्य निर्धारण ने भारत की डेटा खपत को प्रति माह 11.96GB प्रति ग्राहक बना दिया है। 2020 में औसत (ट्राई, 2020), न केवल दुनिया में सबसे अधिक है, बल्कि अमेरिकी स्तरों के 2x से भी अधिक है। पिछले 20 वर्षों में इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी हैवेल्स ने अपने राजस्व में लगभग 100 गुना और उसके मुनाफे में 300 गुना से अधिक की वृद्धि की है और जैसे-जैसे निवेशकों को इसकी क्षमता का एहसास हुआ है, 1 994 में इसकी लिस्टिंग के बाद से इसका मार्केट कैप 6,000 गुना बढ़ गया है। (1997 में अमेज़ॅन के आईपीओ के बाद से एक मज़ेदार तुलना के रूप में, इसका मार्केट कैप अब तक 4,000 गुना बढ़ गया है, जिससे जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं।) इन सबका एक समान विषय है: भारतीय उपभोक्ता। जबकि कुछ आलोचनाएं कहती हैं कि भारतीय क्रय शक्ति सीमित है, उपभोक्ता बाजार प्रभावी रूप से टॉप-डाउन विश्लेषणों में दिखने वाले आकार से छोटे हैं और बाजार खंड तेजी से संतृप्त हो रहे हैं, और मेरी अपनी समझ है कि इसमें जगह बहुत अधिक है। वर्ष 2030 में उपरोक्त से अधिक दिखाई देगा।

भारत के अरबपतियों का मिश्रण उपभोक्ता उछाल की ओर इशारा करता है। ऐतिहासिक रूप से, घरेलू बाजार छोटे, निर्यातक रहे हैं जो उद्योग को प्रिय रहे हैं। भारत के अरबपतियों का उत्पादन करने वाले शीर्ष दस उद्योगों में दो सबसे बड़े योगदानकर्ता सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो दोनों मुख्य रूप से वैश्विक अनुबंध क्षेत्र हैं। शेष अधिकांश उपभोक्ता वस्तुएं और उससे संबंधित क्षेत्र हैं: जैसे तेजी से खपत वाले उपभोक्ता सामान, मोटर वाहन, खाद्य और पेय पदार्थ, कपड़ा और परिधान। और भारत में, अपने एशियाई साथियों से अलग, अचल संपत्ति 10 वीं रैंक पर है और बुनियादी ढांचा सूची में कहीं भी नहीं है।

भारत के अरबपतियों का उत्पादन करने वाले शीर्ष दस उद्योगों में, दो सबसे बड़े योगदानकर्ता सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो दोनों मुख्य रूप से वैश्विक-अनुबंध क्षेत्र हैं।

यह उपभोक्ता-केंद्रित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बल जिसे विरासती व्यवसायों में देखा जा सकता है, व्यवधान की दुनिया में भी सत्य है। अधिकांश बाजार खंडों में कम पैठ स्तर ने उद्यमियों के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन और ओमनी-चैनल मोड में नए उत्पाद और ब्रांड लॉन्च करने के अवसर खोले हैं। भारत में आज 100 यूनिकॉर्न हैं[6], और 2021 में एक महीने में ही 3 नए जोड़े गए[7]। प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस (2021) की रिपोर्ट आशा व्यक्त करती है कि भारत में वर्तमान में 190 "सूनिकॉर्न" हैं जिनके बारे में संभावना है कि वर्ष 2025 तक उनकी स्थिति यूनिकॉर्न में बदल जाएगी। फिनटेक यूनिकॉर्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद खुदरा, ऑनलाइन, क्लासीफाइड, यात्रा, शिक्षा, भोजन, सामग्री और गेमिंग का स्थान आता है। यूनिकॉर्न स्थिति तक पहुंचने में लगने वाला समय, 2010 में औसतन 7.4 साल से घटकर, अब 2.4 साल हो गया है, और मौजूदा ट्रेंड लाइनों के आधार पर 2030 तक 250 यूनिकॉर्न होने की उम्मीद की जा सकती है। मेरा अनुमान है कि: जो घरेलू खपत में उछाल देखने से प्रेरित है, वर्ष 2030 में सबसे अधिक मांग वाली नौकरियां यूनिलीवर या गोल्डमैन सैक्स की नहीं होंगी, जो पारंपरिक रूप से, कैंपस भर्तियों के मामले में पहले दिन से ही शीर्ष पर रही हैं, बल्कि बूटस्ट्रैप्ड, एड्रेनालाईन-संचालित, यूनिकॉर्न आकांक्षी स्टार्टअप होंगे, जिनका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ है।

उपभोक्ता क्षेत्र में दो विपरीत प्रवित्तियों का एक साथ चलना एक सत्य है। नए लेकिन पारंपरिक रूप से संचालित उपभोक्ता ब्रांड असाधारण संपत्ति बनाना जारी रखते हैं। जरा विनी कॉस्मेटिक्स को देखें जो फॉग ब्रांड का डिओडोरेंट बनाता है। या कैंडी व्यवसाय में पल्स को, जिसकी शुरुआत एक सच्चे पारंपरिक पान मसाला कंपनी द्वारा की गई थी। या महिलाओं के परिधान में बीबा, हाथ से बुने कपड़ों और घरेलू सामानों में फैब इंडिया, आयुर्वेद आधारित त्वचा देखभाल में फारेस्ट एसेंशिअल्स, मसालों में एमडीएच, सॉस में वीबा। यह सूची असीमित है। वहीं, कैटेगरी दर कैटेगरी, डिजिटली देशी ब्रांड भी अपनी पहचान बना रहे हैं। बोट के हेडफ़ोन 20 से 29 की उम्र वाले लोगों में एक ललक पैदा करते हैं। Mamaearth के त्वचा देखभाल उत्पादों ने युवा महिलाओं की कल्पना को पकड़ लिया है। लिशियस को अपनी जगह मांस उद्योग में मिली है और वह अबतक असंगठित रहे क्षेत्र में एक प्रत्यक्ष उपभोक्ता ब्रांड बनाने का प्रयास कर रहा है। कंट्री डिलाइट अपनी गहरी आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ डेयरी उद्योग को बाधित कर रहा है। Pharmeasy, एक कंपनी जिसमें हम शेयरधारक हैं, भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फ़ार्मेसी बन गई है, पिछले साल यूनिकॉर्न बन गई, और अब 5-6 अरब डॉलर के मूल्यांकन के आधार पर एक आईपीओ लाने की योजना बना रही है।

5 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, पेज 4

6 देखें100 यूनिकॉर्न: भारत की बदलती कॉर्पोरेट रणनीति इंडिया मार्केट स्ट्रैटेजी क्रेडिट सुइस, 10 मार्च, 2021। आरबीआई बुलेटिन, अगस्त 2021 में उद्धृत।

7 https://www.business-standard.com/article/companies/india-added-three-unicorns-per-month-in-2021-hurun- report-121090200848_1.html

भारत की प्रयोज्य आय (डिस्पोजेबल इनकम) के करण होने वाले उपभोक्ता उछाल का वित्तीय बाजारों में होने वाले बदलाव पर भी गहरा प्रभाव होने वाला है। वर्तमान में 30 सितंबर 2021 को, निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट इंडेक्स में शामिल शीर्ष सात क्षेत्र हैं वित्तीय सेवाएं (37.23% प्रमुख), सूचना प्रौद्योगिकी (17.41%), तेल और गैस (12.30%), उपभोक्ता सामान (11.11%), ऑटोमोबाइल (4.71%), फार्मा (3.39%), और निर्माण (2.69%)8। वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकसित होने के साथ-साथ इस संरचना में बड़े बदलाव होंगे। वित्तीय सेवाओ, तेल और गैस के क्षेत्र का महत्व कम होगा और उपभोक्ता वस्तुओं को स्पष्ट लाभ होगा। कुछ महीने पहले ही, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने इंडेक्स में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पीछे छोड़ दिया था। और इस बात की भी चर्चा है कि रिटेलर DMart और कंज्यूमर इंटरनेट की दिग्गज कंपनी InfoEdge भी जल्द ही इंडेक्स में शामिल होने वाले हैं। ये बदलाव सकारात्मक फीडबैक लूप बनाते हुए भारत की बचत को अंततः निवेश करने के तरीके को प्रभावित करेंगे। कई मायनों में यह दशक भारतीय उपभोक्ताओं का दशक होगा!

2. संरचनात्मक अवरोध और बाधाएं जारी रहेंगी

खपत आधारित वृद्धि को बढ़ावा देने वाली खर्च करने योग्य आय में अनुपातहीन वृद्धि की लगातार प्रवृत्ति का मुकाबला करने में कई चुनौतियां सामने आती हैं जिनको एक समाज के रूप में हम दूर नहीं कर सकते हैं। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि सरकारी नेता अगले दशक के दौरान उन्हें हल करेंगे, हालांकि हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

उत्तर और पूर्व की तुलना में पश्चिम और दक्षिण में आर्थिक गतिविधियों के अंतर से भारत का विकास विकृत होगा। भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य, उत्तरी और पूर्वी राज्यों की तुलना में औसतन, पहले ही, सारभूत रूप से तेज गति से विकास कर रहे हैं। 2019 तक पूर्ण सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारत के तीन सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात थे। फिर आया उत्तर प्रदेश। जब कोई यह मानता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या गुजरात से 3 गुना है और इसकी अर्थव्यवस्था आकार में गुजरात के समान है, तो कहानी चौंकाने वाली हो जाती है[9]। राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद के आधार पर गुजरात की प्रति व्यक्ति आय, उत्तर प्रदेश की तुलना में 3 गुना अधिक है। यहां कुछ और जवाबी सहज ज्ञान युक्त आंकड़े दिए गए हैं: प्रति व्यक्ति आधार पर भारत का सबसे अमीर राज्य गोवा है, जो भारत के सबसे गरीब राज्य, बिहार की तुलना में 10 गुना अधिक अमीर है। पंजाब, जिसको लंबे समय से भारत का समृद्ध राज्य माना जाता रहा है, उसका सकल घरेलू उत्पाद, वर्तमान में, अलग हुए राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तुलना में कम है, यहां तक कि प्रति व्यक्ति आधार पर भी यह तेलंगाना से बहुत नीचे है, और आंध्र प्रदेश के लगभग बराबर है। दरअसल भविष्य धीरे-धीरे और फिर अचानक ही सामने आता है।

> **उत्तर और पूर्व की तुलना में पश्चिम और दक्षिण में आर्थिक गतिविधियों के अंतर से भारत का विकास विकृत होगा।**

इसके कम से कम तीन निहितार्थ होंगे: समृद्धि के विभिन्न स्तरों को देखते हुए, भारत के कुल 4817 विधायकों, - संसद और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सभी सदस्यों - का, भारत को आगे बढ़ाने के तरीके के बारे में आम सहमति तक पहुंचना मुश्किल होगा। इसके अलावा, अगर कोई अमीर और गरीब राज्यों के बीच सांस्कृतिक और भाषाई अंतरों को भी जोड़ लेता है, तो मतदाताओं के अपने भीतर सिमट जाने की संभावना होगी। तमिलनाडु का समृद्ध मध्यम वर्ग आश्चर्य के साथ कहेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता की अक्षमताओं को दूर करने के लिए सब्सिडी देने में उनके कर का पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। बंगलौर या पुणे की शहरी भीड़ - गंदगी और अपराध के खतरे के डर से - बिहार के गरीब प्रवासियों की भीड़ के प्रति ज्यादा दया नहीं दिखा सकती है। चीन और कोरिया में इस तरह की दोष रेखाएं देखी जा चुकी हैं, हालांकि इन देशों ने विनिर्माण क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा की हैं, जबकि भारत में ऐसा कम ही दिखाई पड़ता है, और भाषाई अंतरों को देखते हुए, इन्हें प्रबंधित करना, प्रशासन के सभी स्तरों पर एक अच्छी कलाकारी होगी।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के 2019 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, भारत ने पिछले दशक (2006 और 2016 के बीच)[10] में 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यह संख्या भारतीय आर्थिक आंकड़ों में त्रुटियों और अंतरालों के कारण कभी-कभी विवादित होती है। बहरहाल, गरीबी से निपटने में भारत की असाधारण उपलब्धि कई विसंगतियों को छुपाती है जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने अपनी पिछली पुस्तक "एन अनसर्टेन ग्लोरी" में बताया है। लिंग, जाति और भौगोलिक विषमताएं भारत के गरीबों को परेशान करती हैं। दुनिया में कहीं और की तरह ही भारत में भी बढ़ती असमानता एक बड़ा मुद्दा है।

भारत का गिनी गुणांक - जो आय असमानता का एक मानक माप है - विशेष रूप से हमारे विकास के चरण को देखते हुए, पहले से ही चिंताजनक स्थिति में है। हालाँकि, असमानता की यह तस्वीर पिछले एक दशक के दौरान के उस पश्चिमी अनुभव से बहुत अलग है, जहाँ समाज के एक बड़े हिस्से के जीवन स्तर में उनके मूल की तुलना में गिरावट आई है। भारत और अधिकांश विकासशील देशों को, पूरे मंडल में निरपेक्ष लाभ हुआ है, भले असमान हुआ है। वर्ष 2030 तक भारत के नेताओं को भारत के विकास की विषम प्रकृति का हल निकालना

8 https://www1.nseindia.com/content/indices/ind_nifty50.pdf

9 भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की पुस्तिका, भारतीय रिजर्व बैंक

10 https://gdc.unicef.org/resource/report-india-lifted-271-million-people-out-poverty-decade

होगा और दो मूलभूत प्रश्नों का सामना करना होगा, जिनमें से दोनों प्रश्नों का कोई भी सही उत्तर नहीं है। पहला प्रश्न दार्शनिक प्रश्न है। स्वतंत्रता और समानता के बीच अंतर्विरोध को हल करने की आवश्यकता होगी, इसके बारे में विल डुरंट की उल्लेखनीय पुस्तक "द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री" में प्रकाश डाला गया है। दूसरा प्रश्न राजनीतिक प्रश्न है। पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और एक अज्ञात चीनी मंत्री के बीच चीनी सुधार

2030 तक, भारत के नेताओं को भारत के विकास की विषम प्रकृति का हल निकालना होगा और दो मूलभूत प्रश्नों का सामना करना होगा, जिनमें से दोनों प्रश्नों का कोई भी सही उत्तर नहीं है।

कार्यक्रम के बारे में एक प्रसिद्ध बातचीत में यह पूछे जाने पर कि क्या इससे चीन में अधिक असमानता नहीं पैदा होगी, चीनी मंत्री ने जवाब दिया, "हमें निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद होगी।" वैचारिक रूप से मैं खुद को वाम-आंदोलन का दाहिना हाथ मानता हूँ और सुझाव दूंगा कि केवल राजनीतिक नेताओं या नीति विशेषज्ञों को ही नहीं बल्कि हम में से प्रत्येक को, इस प्रश्न पर एक ठोस, समग्र और व्यावहारिक तरीके से विचार करना होगा। वर्ष 2030 हमारे जवाब का इंतजार कर रहा है।

3. स्मार्ट नीति समाधान और स्वामित्व की भावना महत्वपूर्ण होगी

मेरी पीढ़ी भाग्यशाली रही है कि हमने अपने कामकाजी जीवन की शुरुआत 1991 के सुधारों के बाद की। भारत की विकास दर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी थी। जैसे-जैसे भारत अपने समाजवादी झुकाव को छोड़ता गया और मुक्त बाजारों की गतिशीलता को आत्मसात करता गया, वाम-दक्षिण आर्थिक संवादों में वैचारिक केंद्र की परिभाषा निश्चित रूप से दक्षिण की ओर झुकती गई। यह प्रक्षेपवक्र सभी प्रकार की सरकारों के दौरान जारी रहा है और हाल की नीति घोषणाओं से इसमें तेजी आ गई है। वास्तव में तीस साल पहले की बहसें पुरातन लगने लगी हैं।

जैसे-जैसे भारत अपने समाजवादी झुकाव को छोड़ता गया और मुक्त बाजारों की गतिशीलता को आत्मसात करता गया, वाम-दक्षिण आर्थिक संवादों में वैचारिक केंद्र की परिभाषा निश्चित रूप से दक्षिण की ओर झुकती गई।

व्यवसायियों के रूप में हमें अपनी आर्थिक अपेक्षाओं को बेंचमार्क करने की आवश्यकता है। पहले हमें इसे देश की वास्तविकता से जोड़ने की जरूरत है। आर्थिक सिद्धांत हमें यह बताता है कि वृद्धि की गणना के लिए निवेश दर को वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात से विभाजित किया जाता है। दोनों ही संख्याएँ अस्थिर हैं। एक लंबी अवधि से भारत की निवेश दर लगभग 30% पर मँडरा रही है[11]। निवेश दर का भारत की बचत दर से गहरा संबंध है, जो बदले में आंशिक रूप से सांस्कृतिक और आंशिक रूप से निर्भरता अनुपात से निर्धारित होती है। हमारे उच्च निर्भरता अनुपात के कारण 1960 के दशक में हमारी बचत दर वर्तमान की तुलना में लगभग आधी थी। जब हमारी बचत दर दोगुनी हो गई, तब हमारी वृद्धि दर भी दोगुनी हो गई। भारत का वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात लगभग 4 है और ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसलिए आर्थिक विकास के मामले में भारत का संघर्ष भार 7 और 7.5% के दायरे में है और इसी के लिए उसे प्रयास करना चाहिए।

दूसरा, हमें संभावनाओं के साथ सोचना होगा। हमें परिदृश्यों की कल्पना करनी होगी और नियत रास्तों के बजाय संभावनाओं के साथ काम करना होगा। भारत के विकास में उतार-चढ़ाव इस संख्या के आसपास ही होगा और अगर यह समय-समय पर थोड़े समय के लिए 9% तक चढ़ जाता है या 4.5% तक गिर जाता है तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। दोनों का होना लाजिमी है और चरम विचारों को आमंत्रित करते हैं। जैसा कि भारत की निवेश दर में स्थितिजन्य उतार-चढ़ाव होता रहता है, हमने जीडीपी के आंकड़ों पर इसका प्रभाव देखा है, जिनमें से अधिकांश अल्पकालिक होते हैं। रुडयार्ड किपलिंग से उधार लेकर, हमें विजय और आपदा दोनों का सामना करना और उन दोनों धोखेबाजों के साथ एक जैसा व्यवहार करना सीखना होगा!

तीसरा, अन्य देशों के साथ सतही तुलना एक भ्रामक चीज है। उदाहरण के लिए व्यापारिक हलकों में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि चीन ने लगभग दो दशकों तक 10% की शानदार विकास दर कैसे हासिल की। उत्तर यहाँ है: उस अवधि के अधिकांश समय में चीन की बचत दर 45% थी और इसका वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात लगभग 5 था। गणित सरल था। अत्यधिक कर्जों के द्वारा पोषित वर्षों के उप-सममूल्य निवेशों ने वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात को 7 या अधिक तक बढ़ा दिया[12]। विकास दर गिरकर 6.5% हो गई। जादू खत्म हो गया। इसे एक विफलता नहीं बल्कि परिपक्व अर्थव्यवस्था का कुछ हद तक स्वाभाविक परिणाम मानना चाहिए।

चौथा, भारत की अनुकूल जनसांख्यिकीय खिड़की वह चीज पैदा करेगी जिसे चार्ली मुंगेर "लोलापालूजा" प्रभाव कहते हैं। बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन चार्ली मुंगेर ने इस शब्द को यह बताने के लिए गढ़ा था कि कई अलग-अलग प्रवृत्तियां और मानसिक मॉडल एक ही दिशा में कार्य करने के लिए कैसे गठबंधन बनाते हैं। कम निर्भरता अनुपात, बचत निवेश और विकास के एक आत्म-सुदृढ़ीकरण चक्र को बढ़ावा देगा। कामकाजी उम्र की आबादी में एक उछाल, जो वर्ष 2018 में शुरू हुआ

[11] जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत की निवेश दर में 20% से 35% के बीच उतार-चढ़ाव आता रहता है। एनपीए में वृद्धि के साथ इसे नीचे खींच लिया गया है। हालाँकि, सरकार एसेट क्वालिटी रिव्यू के बाद इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की शुरुआत करके कड़ी कार्रवाई करने में तत्पर है। इनके द्वारा एनपीए को उचित स्तर पर वापस लाना होगा और क्रेडिट चक्र की नई शुरुआत करनी होगी।

था और जिसके 205013 तक चलने की उम्मीद है, टर्बोचार्ज वृद्धि में मदद कर सकता है, जैसा कि 20वी सादी के अंत में कई एशियाई देशों के साथ हुआ था, जिसने दशकों तक लगभग दो अंकों की आर्थिक वृद्धि देखी थी।

सरकारें मायने रखती हैं। कुछ मायनों में, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। अन्य मायनों में, जितना हम सोचते हैं उससे कम। 1990 के दशक की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश की आबादी का 40.85%[14] और संयुक्त आंध्र प्रदेश का 22.19% हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे था। दोनों लीग टेबल में सबसे नीचे थे। बीस साल बाद 2011-12 में उत्तर प्रदेश की गरीबी दर 29.43%[15] थी जबकि आंध्र प्रदेश इसे 9.20% तक कम करने में कामयाब रहा था। राजनीतिक उद्यमिता स्पष्ट रूप से काम करती है। दूसरी ओर,

यदि कोई भारत के आर्थिक विकास के संदर्भ में स्वाभाविक संघर्ष भार के साथ रहता है, तो अल्प से लेकर मध्यम अवधि में सुशासन 1% तक बदल सकता है।

निकट भविष्य में वैश्विक मैक्रो और आर्थिक चक्र शासन से अधिक मायने रखते हैं। यदि कोई आर्थिक विकास के मामले में भारत की स्वाभाविक संघर्ष भार के साथ रहता है, तो सुशासन लघु से मध्यम अवधि में, संख्या में 1% तक बदलाव ला सकता है। वैश्विक स्थितियां- जैसे व्यापार बाधाएं, कमोडिटी की कीमतें, ब्याज दरें- इसे एक बड़े कारक द्वारा बदल सकती हैं। लंबी अवधि में जैसे-जैसे मैक्रो-बल एक-दूसरे को रद्द करते जाते हैं वैश्विक मैक्रो पृष्ठभूमि में चला जाता है। जो बचता है वह है शासन। लोग अक्सर आदतन क्रेडिट और दोष को गलत बताते हैं। राजनीतिक और चुनावी चक्र, केंद्र सरकार या कुछ राज्य सरकारों के चुनावों की आवर्ती हलचल, इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। इसलिए, मेरे दोस्तों आप से एक अनुरोध है: 2022 या 2025 पर नहीं बल्कि 2030 पर ध्यान केंद्रित करें!

आशावाद की गारंटी है। यहां विश्व बैंक से एक आश्चर्यजनक तथ्य है: उनका "लाइव चेंज इंडेक्स" यह ट्रैक करने के लिए कि आबादी ने कितने आर्थिक बदलावों का अनुभव किया है, आजीवन प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग करता है[16]। पिछले तीन दशकों में, चीन ने 31 गुना प्रदर्शन किया है, पोलैंड 9 गुना पर उपविजेता रहा है, और भारत 5 गुना के साथ 6 ठवें स्थान पर, सिंगापुर, मलेशिया और ब्राजील से आगे है। भारत को लंबा खेल अच्छा खेलना जारी रखना होगा।

साथ ही, गति का भी महत्व रहेगा। निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं पर विचार करें: म्यांमार में तख्तापलट, टेक्सास में बिजली संकट, ऑस्ट्रेलिया बनाम फेसबुक, बिटकॉइन 50,000 डॉलर पर पहुंचा, चीन ने बीबीसी पर प्रतिबंध लगा दिया, नासा मंगल पर उतरा, भारत ने कई देशों को टीके भेजे, कोविड के मामलों में पूरे विश्व में गिरावट, बिडेन के

2030 का एक आरोही भारत बहुमुखी तरीके से कार्य करेगा, दूरदर्शिता दिखायेगा और वैश्विक एजेंडा को आकार देगा।

शासन में पहला अमेरिकी हवाई हमला। जैसा कि डेटा शोधकर्ता नॉरबर्ट एलेक्स ने बताया ये सभी फरवरी 2021 के एक ही महीने में हुए। विश्व की घटनाओं की इस तेज गति को देखते हुए 2030 का आरोही भारत बहुमुखी तरीके से कार्य करेगा, दूरदर्शिता दिखायेगा और वैश्विक एजेंडा को आकार देगा।

12 https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/01/22/joyless-growth-in-china-india-and-the-united-states/
13 https://ourworldindata.org/grapher/age-dependency-ratio-projected-to-2100
14 https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=18810
15 https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=18810
16 https://hbr.org/2021/05/chinas-new-innovation-advantage

4. कार्रवाई राजनीति और अर्थशास्त्र के चौराहे पर होगी

एक कहावत है कि "अर्थशास्त्र अर्थशास्त्रियों के लिए छोड़ दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है"। इसे अक्सर विंस्टन चर्चिल द्वारा कहा गया बताया जाता है, लेकिन यहां मैं यूसी बर्कले अकादमी के और क्लिंटन प्रशासन में पूर्व श्रम सचिव रॉबर्ट रीच की प्रसिद्ध मौलिक किताब का जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने बाद के चरण के पूंजीवाद के युग में जिसमें हम रहते हैं, सरकार की भूमिका के बारे में भावुकता के साथ लिखा था। 1960 के दशक की शुरुआत से लेकर 1980 के दशक के अंत तक, दक्षिण कोरिया के "मिरेकल ऑन द हान रिवर" को विश्व इतिहास में अभूतपूर्व माना जाता है और इसका नेतृत्व एक बहिर्मुखी सरकार द्वारा किया गया था। चीन में बदलाव का लंगर, 1970 के दशक के अंत में देंग शियाओपिंग के "अमीर होना गौरवशाली बात है" आन्दोलन द्वारा डाला गया था। जर्मनी, मैक्सिको, चेक गणराज्य, सभी में समान राजनीतिक उत्साही समर्थक थे। भारत में, जैसे-जैसे राजनीतिक शक्ति केंद्र से राज्यों को हस्तांतरित होती जाएगी, शासन सफलता का एक गहरा निर्धारक बनता जाएगा। चाहे सरकार के अनिश्चित वित्त का प्रबंधन हो या प्रत्यक्ष और परोक्ष कराधान के चक्रव्यूह को सुव्यवस्थित करना, चाहे भारत के बैंकों के बहीखाते में डूबे ऋणों की संचित समस्याओं को हल करना हो या वास्तविक दीर्घकालिक ब्याज दरों को उच्च 5% से नीचे लाना जिसने भारतीय व्यापार को प्रभावित किया है, चाहे व्यापार समझौतों की दुनिया को रास्ता दिखाना हो या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में अपनी चीन + 1 योजनाओं पर विचार करना, चाहे भारत के खराब सामाजिक संकेतकों पर विचार-विमर्श करना हो या भारत की राज्य क्षमता को उन्नत करना, चाहे भारत की भू-राजनीतिक स्थिति को आगे बढ़ाना हो या भारत के निजीकरण कार्यक्रम को अनुकूलित करना, चाहे तकनीक-क्षेत्र का विनियमन हो या भारत के 45 मिलियन मामलों के कानूनी बैकलॉग पर कार्रवाई को तेज करना[17], चाहे भारत की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करना हो या भारत की कृषि अक्षमताओं को हल करना, विजेता फॉर्मूला हमेशा राजनीति और अर्थशास्त्र के चौराहे पर ही बसेगा। अर्थशास्त्र तर्क देगा, राजनीति छूट देगी। भारत की जनसांख्यिकी एक वरदान और अभिशाप दोनो है। भारत के लिए अवसर की खिड़की शायद अगले डेढ़ दशक की है। 2025 और 2030 के बीच 65 से अधिक आबादी के अंडर-फाइव समूह से आगे निकलने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा "इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2017" में कहा गया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का हिस्सा 2015 में 8% से बढ़कर 2050 में 19% हो जाएगा। यह सब निर्भरता अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति को उलट देगा, बचत-निवेश-विकास गतिशीलता पर चोट पहुंचाएगा और भारत की आर्थिक विकास दर को सीमित कर देगा। मैंने हाल ही में एक ट्वीट पढ़ा था जो मध्य अमेरिका की भावनाओं को दर्शाता है: "आपके द्वारा ऑर्डर की गई जीवनशैली स्टॉक में नहीं है," यह संभवतः भारत में भी चलेगा। एक तरफ आकांक्षाओं का जमघट और दूसरी तरफ जनसांख्यिकीय उलटफेर के भार के साथ तनाव निश्चित रूप से बढ़ जाएगा।

भारत में, जैसे-जैसे राजनीतिक शक्ति, केंद्र से निकल कर राज्यों को मिलती जाएगी, शासन सफलता का एक गहरा निर्धारक बनता जाएगा।

भारत की जनसांख्यिकी एक वरदान और अभिशाप दोनों है। भारत की अवसरों की खिड़की शायद अगले डेढ़ दशक हैं।

राजनीतिक नेताओं को एक निश्चित बिंदु पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नेतृत्व करना होगा और जटिलता और अनिश्चितता भरी दुनिया में नेतृत्व के संबंध में जिम कॉलिन्स की प्रबंधन सलाह का पालन करना होगा: "अत्यधिक दूरदर्शी कंपनियां "या के अत्याचार" से उत्पीड़ित होने की बजाय, "और की प्रतिभा" - एक ही साथ कई आयामों के दोनों चरम छोरों को अपनाने की क्षमता के द्वारा, खुद को मुक्त कर लेती हैं। विज़न 2030 और उससे आगे के लिए, बक्से बाहर हैं, तरलता अंदर है।

नीतिगत दुस्साहसवाद की पूंछ लंबी होती है। उदाहरण के लिए हाल के समाचार रिपोर्ट[18], हालांकि उनको चुनौती दी गई है[19], दर्शाते हैं कि 2005-10 की अवधि में सरकार द्वारा कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाले घाटे की, जिसका असर उपभोक्ताओं और उद्योग पर पड़ने देने की अनुमति नहीं थी, भरपाई करने के लिए, तेल विपणन कंपनियों को जारी किए गए तेल बांडों से सरकारी वित्त को कैसे नुकसान पहुंचा है। इन्हें, $ 10 से $ 18 बिलियन के बीच अनुमानित, अब 2021 के अंत से ले कर 2026 तक के बीच चुकाना होगा।

17 https://www.news18.com/news/explainers/explained-cji-ramana-says-4-5-crore-cases-pending-heres-what-has-been- fuelling-backlog-3977411.html
18 https://indianexpress.com/article/explained/the-oil-bonds-upa-launched-why-how-much-and-what-nda-argues-7458773/
19 https://scroll.in/article/894559/fact-check-have-upa-era-oil-bonds-prevented-modi-government-from-reducing-oil-prices

केंद्रीय बजट के रचनात्मक प्रबंधन के इस तरह के अभ्यासों ने सरकारी वित्त की अनिश्चितता में वृद्धि कर दिया और प्रभावी ढंग से करदाताओं को, आज एक दशक से अधिक समय पहले उपभोक्ताओं को दी गई सब्सिडी के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे ज्यादातर मामलों में राजनीति जीतती है, अर्थशास्त्र हारता है। कठोर नेतृत्व वाले अर्थशास्त्र को केंद्र में लाने की जरूरत है।

निकट भविष्य में, जबकि राष्ट्रवाद, लोकलुभावनवाद और संरक्षणवाद की मोहक अपीलें जोरदार होंगी, पेंडुलम अंतत: वैश्विक एकीकरण की ओर जाएगा, और इस दशक के समाप्त होने तक निरंकुशता का हमारा अपना ऐतिहासिक अनुभव शायद हमें मुक्त बाजारों और वैश्वीकरण का चैंपियन बना देगा।

राजनीतिक ध्रुवीकरण के आर्थिक समाधान भी हो सकते हैं। एक बहुत ही सामयिक निबंध द अमेरिकन पर्पस में कार्नेगी एंडोमेंट के एक फेलो, स्टीवन फेल्डस्टीन (2021) ने तकनीकी द्वारा संचालित इको चेम्बर्स और सुरक्षित आश्रयों के जोखिमों के बारे में बात की: "यहाँ एक जोखिम है कि लोकतंत्र आगे भी "स्प्लिंटरनेट्स" में टूट जाएगा जो मानदंडों और मानकों को समन्वयित करने में असमर्थ है। भारत में बहुआयामी विविधता के कारण इस तरह के जोखिम और भी अधिक हैं। मूर्त समृद्धि पर एकमात्र ध्यान कथा को दिशा दे सकता है। निकट भविष्य में, जबकि राष्ट्रवाद, लोकलुभावनवाद और संरक्षणवाद की मोहक अपीलें और इस दशक के समाप्त होने तक निरंकुशता का हमारा अपना ऐतिहासिक अनुभव शायद हमें मुक्त बाजारों और वैश्वीकरण का चैंपियन बना देगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को पश्चिम की ओर देखने के लिए तैयार किया गया है। अब ज्यादातर कार्रवाई पूर्व में होती है और जैसे ही भारत पूर्वी एशियाई व्यापार नेटवर्क में दरार डालता है, पुरस्कारों के अनुपातहीन हो जाने की संभावना है।

जैसे-जैसे दुनिया द्विध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ती जाएगी, संरेखण अधिक से अधिक मुद्दा आधारित और रणनीतिक होता जाएगा, जो भारत जैसी बीच की शक्तियों को दुनिया को आकार देने की नई क्षमता देगा।

द लोवी एशिया पावर इंडेक्स (2020) आठ मानदंडों के आधार पर देशों को रैंक देता है: आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलापन, भविष्य के संसाधन, आर्थिक संबंध, रक्षा नेटवर्क, राजनयिक संबंध और सांस्कृतिक प्रभाव। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये सभी कारक राजनीतिक और आर्थिक ताकतों का संगम हैं। 2020 के सर्वेक्षण में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद 4 स्थान पर है। 2030 तक भारत आसानी से अगर 2 सरे नहीं तो 3 सरे स्थान पर आ सकता है। भू-राजनीतिक रूप से भारत का उद्घाटन होगा: जैसे-जैसे दुनिया द्विध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ती जाएगी, संरेखण अधिक से अधिक मुद्दा आधारित और रणनीतिक होता जाएगा, जो भारत जैसी बीच की शक्तियों को दुनिया को आकार देने की नई क्षमता देगा। हालाँकि, इसका फायदा उठाने के लिए एक एकीकृत विश्वदृष्टि की आवश्यकता होगी, जिसके मूल में राजनीतिक शिल्प कौशल, भारतीय प्रवासी की गहरी जड़ों से सहायता प्राप्त और प्रेरित, भारत की आर्थिक ताकत, और भारत की चीन का मुकाबला करने के लिए निकट प्राकृतिक स्थिति होगी।

दुनिया की सबसे छोटी कविता - मी, वी - हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन मुहम्मद अली ने हार्वर्ड कमेंसमेंट (हार्वर्ड की शुरुआत) में 1975 में पढ़ा था। यह आत्मविश्वास और समुदाय के प्रति सम्मान के विरोधाभास को दर्शाती है। 2030 तक के दशक में भारतीय नेताओं को ऐसी कविता सुनाने की आवश्यकता होगी।

5. निष्कर्ष: जीत के लिए, कैथेड्रल थिंकिंग का अभ्यास करें

2030 का आर्थिक पुरस्कार पहली नज़र में शायद उतना आकर्षक न लगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल्स (2021) के अनुसार, 2030 में भारत की जीडीपी 6.2 ट्रिलियन डॉलर होगी, जो प्रति व्यक्ति आधार पर 4185 डॉलर होगी। हालांकि, पीपीपी आधार पर, यह आज इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका या पेरू की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक होगा। एक समाज के रूप में हमें इस आधार मामले को मात देने का प्रयास करना चाहिए। वहां पहुंचने के लिए कैथेड्रल थिंकिंग की आवश्यकता होगी।

कैथेड्रल थिंकिंग दीर्घकालिक, दूरदर्शी कार्य को संदर्भित करता है जिसे पूरा करने में पीढ़ियां लग सकती हैं। एक विशाल गिरजाघर के निर्माण की तरह, जो पहले पत्थर रखते हैं, वे तैयार उत्पाद का स्वाद लेने के लिए नहीं होंगे। फिर भी प्रत्येक कार्यकर्ता किसी ऐसी चीज के लिए सार्थक योगदान करने के लिए प्रेरित होता है जिसका आनंद आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, जिनसे वे कभी नहीं मिलेंगे। भारत को अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी के विजन देखने वाले नेताओं की जरूरत है।

जो लोग सोचते हैं कि किसी देश का आर्थिक भाग्य भूगोल या संस्कृति से निर्धारित होता है, उनके लिए डारोन एसेमोग्लू और जिम रॉबिन्सन (2012) के पास एक बुरी खबर है। अपनी उल्लेखनीय पुस्तक, "व्हाई नेशंस फेल" में वे दो हजार वर्षों के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का वर्णन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई देश अमीर है या गरीब, इसका प्रमुख निर्धारक मानव निर्मित संस्थाएं हैं, संसाधन या बंदोबस्ती या इतिहास की आकस्मिकताएं नहीं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के नए युग के लिए भारत के संस्थानों की संरचना को बदलने की आवश्यकता है।

कुछ चीजें बाहर खड़ी हैं। भारत के संस्थानों को आम तौर पर कई परस्पर विरोधी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है। नियामक अक्सर बाजार की वास्तविकताओं के साथ पकड़ बनाते हैं। कई सरकारी नीतियों के संदर्भ में फ्रेम में ही संकट होता है। और अंत में भारत के निर्णायक क्षणों में व्यक्तिगत वीरता संस्थागत पहलों को मात दे देती है। 2030 का भारत एक संस्थागत व्यवस्था से बहुत अलग दिखाई देगा और संभवत: हमारे सामने आने वाले सभी सतही परिवर्तनों का मुख्य चालक होगा।

2030 का भारत एक संस्थागत व्यवस्था से बहुत अलग दिखाई देगा और संभवत: हमारे सामने आने वाले सभी सतही परिवर्तनों का मुख्य चालक होगा।

सफलता - लोगों, व्यवसायों, देशों की - अधिक सौभाग्य, कम दुर्भाग्य, भाग्य के उच्च शिखर, या भाग्य के बेहतर समय का परिणाम नहीं होती है। इसके बजाय वे दूसरों की तुलना में अपनी किस्मत ज्यादा बनाते हैं। वर्तमान दशक भाग्य पर अपने लाभ को अधिकतम बनाने का समय है!

हवाले (सन्दर्भ)

256 नेटवर्क और प्रैक्सिस ग्लोबल एलायंस। (2021). विचारों को सोने में बदलना। स्रोत url:https://www.praxisga.com/reports-and-publications/financial-investors-group/report-turning-ideas-to-gold

एसेमोग्लू, डी. और रॉबिन्सन, जे.ए. (2012). राष्ट्र विफल क्यों होते हैं: शक्ति, समृद्धि और गरीबी की उत्पत्ति। न्यूयॉर्क: क्राउन पब्लिशर्स, रैंडम हाउस।

कोलिन्स, जे. और पोरस, जे.आई. (1994). बिल्ट टू लास्ट: सक्सेसफुल हैबिट्स ऑफ़ विजनरी कंपनीज. संयुक्त राज्य अमेरिका: हार्पर बिज़नस. आईएसबीएन 0-060-56610-8

द्रेज, जे. एंड सेन, ए. (2013)। एक अनिश्चित महिमा: भारत और उसके अंतर्विरोध. न्यू जर्सी: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
डुरंट, डब्ल्यू. और ड्यूरेंट, ए. (1968)। इतिहास के सबक। साइमन एंड शूस्टर।

फेल्डस्टीन, एस (2021)। क्या लोकतंत्र "स्प्लिंटरनेट?" से बच सकता है। अमेरिकन परपज. स्रोत url: https://www.americanpurpose.com/articles/can-democracy-survive-the-splinternet/

इण्डिया एजिंग रिपोर्ट (2017) केयरिंग फॉर आवर एल्डर्स: शुरूआती प्रतिक्रियाएं, https://india.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/India%20Ageing%20Report%20-%202017%20%28Final%20Version%29.pdf पर उपलब्ध हैं।

लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स. (2020). लोवी संस्थान स्रोत: https://power.lowyinstitute.org/

पिच मैडिसन एडवरटाइजिंग रिपोर्ट 2019। स्रोत url: https://www.exchange4media.com/PMAR19-Final.pdf प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। (2 सितंबर, 2021)। भारत ने 2021 में प्रति माह तीन 'यूनिकॉर्न' जोड़े हैं: हुरुन रिपोर्ट।

बिजनेस स्टैंडर्ड।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020. https://www.ril.com/getattachment/299caec5-2e8a-43b7-8f70-d633a150d07e/AnnualReport_2019-20.aspx

भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन.अगस्त 2021 वॉल्यूम LXXV नंबर 8. स्रोत url: https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/0BULLETINAUG2021767F2556D32A4061B0AC0EE3C54C1208.PDF

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। (2020). भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक, जुलाई- सितंबर 2020. नई दिल्ली। स्रोत url: https://www.trai.gov.in/sites/default/files/QPIR_21012021_0.pdf

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। (2019). 2019 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास कि एक पहल। स्रोत url: http://hdr.undp.org/en/2019-MPI

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 2017। 'केयरिंग फॉर आवर एल्डर्स: अर्ली रिस्पांस' - इंडिया एजिंग रिपोर्ट - 2017. नई दिल्ली, भारत: UNFPA. स्रोत url: https://india.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/India%20Ageing%20Report%20-%202017%20%28Final%20Version%29.pdf

विरमानी ए. 2004. *भारत की आर्थिक वृद्धि:* समाजवादी विकास दर से भारतीय विकास दर तक, (नं. 122).

आईसीआरआईईआर वर्किंग पेपर।

विश्व आर्थिक लीग तालिका (2021)। स्रोत https://cebr.com/wp-content/uploads/2020/12/ WELT-2021-final-23.12.pdf

ज़ैक डाइक्थवाल्ड। (2021). चीन का नया नवाचार लाभ *हार्वर्ड व्यापार समीक्षा.* स्रोत url: https://hbr.org/2021/05/chinas-new-innovation-advantage

परिशिष्ट

तालिका 1: उपभोक्ता टिकाऊ सूचकांक

वर्ष	उपभोक्ता टिकाऊ सूचकांक
2012-13	104.9
2013-14	110.8
2014-15	115.2
2015-16	119.1
2016-17	122.6
2017-18	123.6
2018-19	130.4
2019-20	119.0
2020-21	101.2

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

तालिका 2: देशों में गिनी इंडेक्स

देश का नाम	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ब्राजील	52.9	53.5	52.8	52.1	51.9	53.3	53.3	53.9	53.4
चीन	42.4	42.2	39.7	39.2	38.6	38.5			
इंडोनेशिया	39.7	39.7	40	39.4	39.7	38.6	38.1	38.7	38.2
भारत	35.7								
मेक्सिको		48.7		48.7		46.3		45.4	

स्रोत: विश्व बैंक

तालिका 3: निवेश (जीडीपी के% में)

वर्ष	निवेश (जीडीपी के% में)
2000-01	22.85%
2001-02	26.63%
2002-03	25.47%
2003-04	24.83%
2004-05	25.64%
2005-06	27.66%
2006-07	29.15%
2007-08	31.50%
2008-09	31.53%
2009-10	31.48%
2010-11	32.22%
2011-12	34.31%
2012-13	33.44%
2013-14	31.30%
2014-15	30.08%
2015-16	28.73%
2016-17	28.19%
2017-18	28.18%
2018-19	29.19%
2019-20	28.75%
2020-21	27.09%

स्रोत: MOSPI

लेखक के बारे में

गौरव डालमिया सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बोर्ड के सदस्य हैं। वह डालमिया ग्रुप होल्डिंग्स के अध्यक्ष हैं जो कि व्यापार और वित्तीय संपत्तियों के लिए एक होल्डिंग कंपनी है। यह निजी इक्विटी, रियल एस्टेट, सार्वजनिक बाजारों, संरचित ऋण और निश्चित आय में निवेश करती है। वह न्यूयॉर्क में द इंस्टीट्यूट फॉर न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य और ग्लोबल एजुकेशन चैरिटी इंडियन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ रूम टू रीड के अध्यक्ष भी हैं। वह द इकोनॉमिक टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द फाइनेंशियल टाइम्स में एक ऑप-एड योगदानकर्ता हैं। गौरव डालमिया को 2000 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा 'कल का वैश्विक नेता' चुना गया था। गौरव डालमिया ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से बीटा गामा सिग्मा ऑनर्स के साथ MBA किया है।

आत्मनिर्भरता | सत्यनिष्ठा | प्रभाव

सेंटर फॉर सोशल एंड इकनोमिक प्रोग्रेस

6, डॉ जोस पी. रिज़ल मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110021, भारत

@CSEP_Org @csepresearch www.csep.org